



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]
No. 179]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4 1985/ भाद्र 13, 1907
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1985/BHADRA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बखरा संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य प्रशासन

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

निर्यात आयात नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 28-ईट सं (पी एन)/85

विषय :- 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक संयुक्त
राज्य अमेरिका, यूरोप आधिक सहाय के सदस्य राज्यों,
ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को बुने मयान्य
लाइसेंस-3 के अन्तर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए
गए वस्त्रों को निर्यात करने के लिए स्कीम।

फा० सं० 2/65/P/85-ई यह स्कीम तैयार पोशाकों और सलाई
से बुने हुए वस्त्रों के कतिपय मर्कों के संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप
आधिक सहाय के सदस्य राज्यों (जर्मन गणतन्त्र संघ, फ्रान्स, इटली,
बेनिक्स, यू० के०, आयरिश गणतन्त्र, डेनमार्क और ग्रस) ऑस्ट्रिया,
फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा का 1 जनवरी 86 से 31 दिसम्बर
1986 तक के अवधि के लिए निर्यात से संबंधित है।

2. योजना को प्रशासित करने के लिए अधिकरण (1) जब तक अन्यथा
रूप से निदेश न दिया जाए, तब तक परिधान निर्यात संबंधित परिषद

(ए०ई०पी०सं०) निर्यात हक्कारियों का आबंटन करेगा और इस योजना
के अंतर्गत आने वाले वर्ष पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए
आवश्यक प्रमाणन करेगा, परन्तु सलाई से बुने हुए ऊर्तों वस्त्रों का आबंटन
ऊन और ऊर्तों निर्यात संबंधित परिषद, नई दिल्ली (इम्पू एंड इम्पू,
ई०पी०सं०) द्वारा किया जाएगा। लेकिन सलाई से बुने हुए वस्त्रों के
संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संबंधित परिषद द्वारा किया
जाना रहेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों
के सूचियां परिधान निर्यात संबंधित परिषद और ऊन और ऊर्तों निर्यात
संबंधित परिषद के पास उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि
योजना के प्रशासन के लिए अधिकरणों के संबंध में ऐसा वह उचित समझे
परिवर्तन कर सकता है।

(2) निर्यात हक्कारों केवल उन निर्यातकों के ही अनुमति होगा जो
कि सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।

3. आबंटन के प्रणाली और मात्रा (1) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक
के सामने संकेतित दर पर नमूनेविधि प्रणाली के अनुसार आवंटित की
जाएगी :-

प्रणाली

वार्षिक स्तर का

(क) भुक्तान म निष्पादन

प्रतिशत

65

- (घ) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश 25
 (ग) विनिर्माता/निर्यातक 7
 (घ) केन्द्र/राज्य निगम 3

(2) यदि सरकार उचित समझे तो उसे द्विपक्षीय समझौते में दाखिल उद्योगों का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4 आरंभ वर्ष का विभाजन तथा अवधियों के बीच मात्रा का बहिर्भाजन (1) भूतकालीन निष्पादन हकदार पद्धति के मामले में, वर्ष को दो अवधियों में बांटा जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक और दूसरी अवधि 1 मई से 30 सितम्बर तक होगी। कुल हकदार का कम से कम 50 प्रतिशत प्रथम अवधि के अंतर्गत उपयोग में लाया जाना चाहिए। शेष 50 प्रतिशत अप्रत्यक्ष स्वतः अर्जित किया गया होगा। जब तक कि वह अन्वया रूप से बढ़ाई गई गारन्टी में न जोड़ा गया हो। विनिर्माता निर्यातक हकदार पद्धति के लिए 1 जनवरी से 30 सितम्बर तक एक अवधि होगी। कंडिका 15(3) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार आरंभ 30 सितम्बर से आगे की वैध किया जा सकता है। भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अंतर्गत कुल आरंभ को 30 सितम्बर, 1986 में पहले उपयोग करना होगा। प्रत्येक वर्ष हुई मात्रा यदि कोई होगी तो जब तक उसकी वैधता कंडिका 15(3) के प्रावधान के अनुसार नहीं बका की जाएगी वह स्वतः ही अर्जित कर दी समझा जाएगी।

(2) केन्द्र/राज्य निगम और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेशों की प्रणाली के मामले में बुनी हुई मर्चों के मामले में वर्ष बार-2 माह की तीन अवधियों में अर्थात् जनवरी—अप्रैल, मई—अगस्त और सितम्बर—दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा और मलाई से बुनी हुई मर्चों के मामले में दो अवधियों अर्थात् जनवरी—अगस्त और सितम्बर—दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा। केन्द्र/राज्य निगम प्रणाली के मामले में बुनी हुई मर्चों के लिए मात्राएं 50: 35: 15 के अनुपात में तीन अवधियों में वितरित की जाएगी, और पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के मामले में वार्षिक स्तर का 15 प्रतिशत प्रथम अवधि में 7 प्रतिशत दूसरी अवधि में 3 प्रतिशत तीसरी अवधि में वितरित किया जाएगा। जबकि मलाई से तैयार मर्चों के लिए मात्रा दोनों पद्धतियों में 8.5: 15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रसान को देखते हुए सरकार पुनः समायोजित कर सकती है।

5. खण्डों की आरक्षण रचना (1) पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों तथा केन्द्र/राज्य निगमों की पद्धतियों के मामले में जहां पर आरंभ मलाई से बुने हुए पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है, वहां उपलब्ध 10 प्रतिशत की मात्रा मलाई से बुनी हुई पोशाकों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

(2) बच्चों की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओं का 10 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) ऊर्ध्व पोशाकों के लिए यह आरक्षण विशिष्टकृत देशों और श्रेणी की मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इसकी घोषणा वस्त्र आरक्षक द्वारा की जाएगी।

6 भूतकालीन निष्पादन प्रणाली

भूतकालीन निष्पादन हकदारों की परिगणना करने के लिए अधिकरण (1) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अधिकरण वस्त्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (एईपीसी) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रियाविधि का निर्धारण करेगा और ए. ई. पी. सी. के कार्य का मंचन करेगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारों के लिए पात्रता प्रणाली : (2) 1986 वर्ष के लिए भूतकालीन, निष्पादन प्रणाली के अधीन कोई निर्यातक किसी मात्रा के आरंभ के लिए केवल तब पात्र होगा जबकि उसने तीन वर्षों अर्थात्, 1983, 1984 और जनवरी—जून 1985 में से किन्हीं दो वर्षों के दौरान संबंधित देश/श्रेणी में निर्यात किया हो।

आधार अवधि और सीमा : (3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1983, 1984 और जनवरी—जून, 1985 की आधार अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के यथानुपात के लिए निर्धारित किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आरंभ सम्बद्ध देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यातक के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाव में होने वाले किसी भी परिवर्तन के मामले में यथानुपात मात्रा की पूर्ण प्रक्रिया पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्यातक की हकदारी में उचित समायोजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारों का हस्तान्तरण : (4) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 30 सितम्बर 1986 तक किसी भी समय या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में पोशाकों के अन्य पंजाब निर्यातक की निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरण की जा सकती है।

(क) भूतकालीन निष्पादन हकदारों के सभी हस्तान्तरण केवल हस्तान्तरण द्वारा 10 प्रतिशत बैंक गारन्टी के प्रस्तुत करने पर ही अनुमति दिए जाएंगे।

(ख) हस्तान्तरण को हस्तांतरित मात्रा के निर्यात के लिए 60 दिन की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश/श्रेणी में दूसरे निर्यातक को हस्तांतरित की हो वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक के हस्तान्तरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तान्तरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) भूतकालीन निष्पादन का हकदार व्यक्ति जो किसी देश/श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" के लघु आदेशों की पद्धति के अंतर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है, वह इस प्रकार के छोटे आदेशों की हकदारी प्राप्त करने के बाद उस देश/श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी में किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(च) हस्तान्तरण के पास हस्तांतरित हकदारियां अन्य सभी प्रकार से उन्हीं नियम और शर्तों के अधीन होंगी जो हस्तान्तरण के लिए लागू हैं।

7. पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति : इस पद्धति के अंतर्गत मात्रा का आरंभ पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और साखपत्रों द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों के सहित किया जाएगा। साखपत्र वैध प्रचलित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। साखपत्र में साफ साफ उस आदेश का संकेत होना चाहिए जिसके सहित साखपत्र खोले गए हैं। मात्रा का आरंभ केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा। लघु आदेश वे हैं, जो विभिन्न देश/श्रेणियों के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिमाणालम्बक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हों। ऐसी परिमाणालम्बक सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अंतर्गत आरंभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) 1986 के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत आरंभ के लिए आवेदन करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (या मलाई से बुने हुए ऊर्ध्व वस्त्रों के लिए ऊर्ध्व

और उन्हीं वस्त्र निर्माण संवर्धन परिषद के माध्यम 31 दिसम्बर, 1953 को या इससे पहले पूर्ण होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/श्रेणी के लिए केवल एक आवेदन पत्र भेजा जा सकता है। लेकिन एक से अधिक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन पत्रों में आने वाली मात्रा निर्धारित मात्रिक सीमा के भीतर हो। प्रथम अवधि के लिए आवेदन पत्र 1 दिसम्बर, 1955 को प्राप्त किए जाएंगे परन्तु आबंटन 1 जनवरी, 1956 में किए जाएंगे।

(3) इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन 60 दिनों की अवधि के लिए किए जाएंगे। तब तक जब तक कि आबंटन केवल 60 दिन या 61 दिसम्बर, 1956 इनमें जो भी होवे हो उस तक बढ़ेगा।

(4) आवंटन पहले आए या पहले पाए के आधार पर मजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपर्युक्त मात्रा अतिपूर्यकोत हो जाएगी, उस दिन पात्रता का निर्णय उच्चतर हस्त मूल्य श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निर्यात हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश/श्रेणी के लिए पैरा 6(3) के अनुसार यथा परिस्थिति अपनी भूतकालीन निर्यात हकदारी का से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसके लिए भूतकालीन हकदारी समस्त शेष अध्यापित करने का भी विकल्प होगा कि यह संबंधित देश/श्रेणी का है और तब वह पहले आए सो पहले पाए कि यह संबंधित देश/श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/श्रेणी में अपने भूतकालीन निर्यात हकदारी से किसी प्रकार का हस्त-तरण नहीं किया है।

(6) निर्यात निर्यातक हकदारी के धारक को पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने के लिए अपने ऐसे हकदारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या उसे अर्पित करना पड़ेगा।

(7) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अंतर्गत आबंटन/वितरण के लिए आवेदन इस संबंध में एक शपथपत्र देगा कि आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1935-38 के पैरा 120 में यथा परिभाषित उसकी किसी भी सहयोगी व्यापार संस्था ने इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कि उस के स्वामित्व के अधीन किसी अन्य स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है। आगे, प्रथम अवधि के आबंटन के लिए आवेदनक इस संबंध में भी शपथपत्र देगा कि उनकी कोई भी सहयोगी व्यापार संस्था कोई भी भूतकालीन निर्यात हकदारी नहीं रखती है।

8 विनिर्माता-निर्यातक पद्धति — इस पद्धति के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 7 प्रतिशत तक की मात्रा का आबंटन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि भूतकालीन निर्यात और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अंतर्गत विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आबंटन पैरा 6(3) के अनुसार निकाले गए उसके औसत वार्षिक भूतकालीन निर्यात के 110% से अधिक नहीं होगा। स्तर के 55% की मात्रा भूतकालीन निर्यात के आधार पर आबंटन की जाएगी और शेष 50% विनिर्माता-निर्यातक की निर्माण क्षमता के आधार पर इस पद्धति के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त आबंटन के लिए पात्रता का निर्णय करेगा जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

9. केंद्रीय/राज्य निगम प्रणाली केंद्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केंद्रीय राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हस्तकरियां विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 3% का विशेष आबंटन किया जाएगा। लेकिन यह आबंटन इन निगमों/उच्च स्तरीय समितियों द्वारा केवल संबंधित निर्यातों के लिए होगा। इस प्रणाली के अधीन आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्रीय/राज्य निगमों को अपने संरक्षण में उत्पादन करना चाहिए। यदि ऐसी निगम के पास उनके

संरक्षण के अधीन उत्पादन सुविधाएं नहीं हैं तो उन्हें सूक्ष्म निर्यातकों या उन विनिर्माताओं द्वारा विनिर्माण नहीं करना चाहिए। अधिकारी अन्य निर्यातकों को पहले से मात्रा सम्भरण कर रहे हैं। तथापि, ये शर्तें सब गति वाली मर्दों के संबंध में लागू नहीं होंगी। निगम/शिखर समितियां भी पूर्व निर्यात और आबंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेश की पद्धतियों के अधीन मात्रा के आबंटन के लिए नीति में बांटे गई शर्तों को पूरा करने के लिए अर्थात् पात्र होंगे। वस्त्र आयुक्त निगम/शिखर समितियों को हकदारी निश्चित करना।

10 सब गति वाली मर्दों सब गति वाली मर्दों को पट्टावत के लिए 1955 के प्रथम चार महीनों का और 1954 का निर्यात हिस्सा में विभाजित जाएगा। यदि संदर्भ के अंतर्गत इस अवधि के दौरान किसी मर्द का निर्यात 1955 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्व 1954 के दौरान निर्धारित कोटे के 75% से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद भी मर्दों में मर्दों जाएगा। लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यह मर्दों की प्रकृति और वास्तविक स्तर के उपयोग की प्रकृति के अनुसार ऐसा समायोजन हुआ तो सरकार कसौटी में परिवर्तन करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना में अत्यंत दी गई किमो अन्य बातें जो पत्र हुए भी मद गति के रूप में शोषित मर्दों के तब से निर्यातित छूट उपलब्ध होंगी —

(1) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत पात्रता के लिए वर्ष के दौरान किमो भी समय परिभाषित निर्धारित संवर्धन परिषद के पास परीक्षण किया जा सकता है।

(2) मात्रा पत्र निर्धारण ऊंचरी नहीं होगा।

(3) निर्यातक की सामान्य वैन गारण्टी/विनिर्माण छन निर्यात के अंतर्गत में 10% का वेगरी वैन विनिर्माण/वेग गारण्टी प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(4) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत पत्र के मामले में निर्धारित मात्रिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। एक देश/श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(5) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अंतर्गत लघु शिखरों का उत्पादन सब गति वाली मर्दों के लिए, उस आवेदन अवधि के अंत तक के लिए वैध होगा जिसके दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(6) मद गति वाली मर्दों के बन्धों की पोशाकों के लिए अलग न्यूनतम मूल्य हो सकता है।

11 उन श्रेणियों का आबंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं है ऐसी श्रेणियों के अधीन विशिष्ट सीमा मात्रा जो विशेष सीमा की शर्तों के अधीन नहीं आती किन्तु यू.एस.ए. के तारे यु.एस. 2 की सीमा के अधीन आती है का आबंटन सभी चार पद्धतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही माना किया जाएगा।

उपर्युक्त पद्धति के अधीन संवेदनशील मर्दों के संबंध में निम्न लागू सभी शर्तें ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होंगी। ऐसा आबंटन ऐसी उन शर्तों के भी अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी के निर्माण शुरू करने की दिशा में निर्धारित की जाएं। ऐसे नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली मर्दों में विशिष्ट या असाई नियंत्रण के अधीन आने वाली मर्दों के लिए भूतकालीन निर्यात हकदारी या विनिर्माता हकदारी में परिवर्तन और वगैरह समानता (एस.वाई.ई.) के अनुसार अनिवार्य मर्दों में भी परिवर्तन की अनुमति परिधान निर्धारित संवर्धन परिषद द्वारा सीमा के अधीन हो आ सकती है।

12 न्यूनतम निर्धारित (न्यूनतम) मूल्य — स्टेन दग/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे। उनकी निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित मर्दों

पर ध्यान दें जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को संवत् १९८० वाली मर के रूप में अतिरिक्त किया गया है या नहीं।

13 निर्यात हस्ताक्षरों के उत्पादन की वैधता अवधि — जहाँ वैधता अवधि पैरा 7(3) में दिये गए के अनुसार होगी, खदान बिल पर उत्पादन पहले आए सो पहले पाए छोटे आवेदन पत्रों के मामले के अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

14 साख पत्र — सभी पोशाकों और सजाई से बने हुए वस्त्रों के लिए आर्बटन साख पत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साख पत्र प्रचालित, वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए सख आवेदों और के डीएम/राज्यों निगम पद्धतियों के मामले में साख पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भूतकालीन निष्पादन हकदारों और विनिर्माता निर्यातक हकदारों पद्धतियों के मामले में साख पत्र प्रमाणन के समय भेजने चाहिए। मद गाँव वाली मर के लिए साख पत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 10 में दिया गया है।

15 पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी और उनकी जमा करना — (1) भूतकालीन निष्पादन पद्धति के मामले में निर्यातक को जनवरी-अप्रैल, 1986 के अवधि के दौरान पोतलदान की गई मात्रा के लिए पेशगी धन निक्षेप या बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगी। उसे 30-4-1986 को या उससे पहले भूतकालीन निष्पादन हकदारों के 50% का उपयोग कर लेना चाहिए। इस हकदारों के अप्रयुक्त भाग को दूसरी अवधि के दौरान 15% के बैंक गारण्टी के साथ आगे ले जा सकता है। उसे 31-7-86 को या इससे पहले भूतकालीन निष्पादन हकदारों का 75% उपयोग कर लेना चाहिए। इस हकदारों के अप्रयुक्त भाग को 30-9-86 तक 15% का बैंक गारण्टी के साथ आगे ले जा सकता है।

(2) विनिर्माता निर्यातक पद्धति, के मामले में निर्यातक को जनवरी-अप्रैल, 1986 अवधि के दौरान पोतलदान की गई मात्रा के लिए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी। 30-4-86 के बाद उनकी निर्यात हकदारों के अहाज पर निशुल्क मूल्य की 10% की सीमा तक पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। ऐसी पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य तथि 30-4-86 होगी।

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारों और विनिर्माता निर्यातक हकदारों की वैधता 30 सितम्बर तक प्रतिबंधित होगी। लेकिन यह वैधता अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20% की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन साख पत्र द्वारा समर्थित विशेष क्षेत्रों के लिए 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ाई जा सकता है।

(4) एस सी एक एस छोटे आवेदों और के डीएम/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में, निर्यातक को आवेदित मात्रा के अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% की दर पर ई एस डी/बैंक गारण्टी द्वारा समर्थित निष्पादन बांध देना होगा।

(5) एक निर्यातक जो विनिर्माता निर्यातक पद्धति या एक विशिष्ट अवधि में आर्बटन की अन्य पद्धतियों के अधीन 30-9-86 को या इससे पूर्व उसे आवेदित निर्यात हकदारों के 90% तक का निर्यात करता है जिसमें पूर्व निष्पादन हकदारों शामिल नहीं होगी, उसका ई एस डी/बैंक गारण्टी जमा नहीं होगी। जो निर्यातक 75% तक किन्तु 90% से कम निष्पादन करता है उसका कुछ अंश जमा किया जा सकता है। यदि निर्यात हकदारों आर्बटन का उपयोग 75% से कम है तो निर्यात की पूरी ई एस डी/बैंक गारण्टी जमा की जा सकती है। पूर्व निष्पादन निर्यात पद्धति के मामले में, इस प्रकार पेशगी धन निक्षेप बैंक गारण्टी के अन्तर्गत आने वाली मात्रा का 90% भाग उपयोग में नहीं लाया गया तो पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी जमा हो जाएगी। 30-9-1986 तक पूर्व निष्पादन हकदारों और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के अधीन पुनर्विक्रीकरण के मामले में, यदि व्यक्तिगत संविदा के अन्तर्गत 90% की मात्रा तक उपयोग में

नहीं लाई जाती है तो बैंक गारण्टी/ई एस डी की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर ली जाएगी। ये प्रावधान जब भी शुरू हों, अनिवार्य मरता की शर्तों के अधीन होंगे।

(6) के डीएम/राज्य निगमों के मामले में जहाँ उपयोग वैधता अवधि के दौरान 75% से कम नहीं है, निर्यातक को निर्यात हकदारों वर्ष के दौरान अगली आर्बटन अवधि के लिए समयवृद्धि लेनी होगी। ऐसी समयवृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बन्ध आर्बटन अवधि के अन्त से एक मास के भीतर शामिल करने चाहिए। ऐसे मामलों में निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धनराशि जमा करनी होगी। बैंक गारण्टी वेनी होगी। पूर्ण रूप से निर्मित करने में व्यय होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी पूरी तरह जमा हो जाएगी।

(7) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आवेदित किए जाते हैं, कि तु वे उनका पूरा पूरा उपयोग नहीं करने हैं तो वे पत्र में जा कुछ अन्य कार्यवाही की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें अपने कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

16. पेशगी के धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी जमा करने के विरुद्ध अपील — आवेदित निर्यात हकदारों के उपयोग में न के लिए पेशगी को धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी के जमा करने के लिए निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए अनिवार्य किया-विधि लागू होगी। परिधान निर्यात संबंधन परिषद के पेशगी के धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी जमा किये जाने पर संबंधित ऐसे जमाकरण का सूचना प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर सूचना देना, बम्बई वा उनके विरुद्ध अपील कर सकता है। अपील आर्बटन, प्रावधान प्रदा होने के बाद मात्र से मात्र निर्णय देंगे। पत्र के मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो 15 दिनों के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है और अपील विभाग को क जाएगा और उस पर सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत द्वारा विचार किया जाएगा।

17. 30 सितम्बर से उपलब्ध मात्रा की शक्ति — इस सा धनिक सूचना में किस भी अवधि में पर निहित कि सा नियम को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर की उपलब्ध शेष मात्रा, चाहे वह बिना शर्तों से या अभ्यर्ण से प्राप्त हो, एक सामान्य उद्देश्य में मिलाई गई समझा जाएगा और विभिन्न विभागों के लिए किसी आवेदन के बिना पहले आए सो पहले पाए सख आवेदन पत्रों के अधीन उस मात्रा का बांटा जाएगा।

18. निर्यात हकदारों आर्बटन का पर्यवेक्षण — वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारों के आर्बटन से संबंधित मामलों पर दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे, और संबंधित निर्यात संबंधन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय-समय पर नीति के परिष्कार की पुनरीक्षा करेंगी। विचारों में विविधता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

19. सीमा शुल्क द्वारा निकासी — (क) निर्यात के अधीन उत्पाद जिसमें वे नहीं हैं शामिल हैं जो यू एस ए में विशिष्ट मर्चों के अधीन न हों। पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्रों पर परिधान निर्यात संबंधन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेशनों के लिए मूल पोतलदान बिलों पर और उनकी अनुमति प्रति पर पुष्टीकरण के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद — जहाँ तक कनाडा को निर्यात मर्चों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों और घास्ट्रिया को सूची हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, जहाँ सीमा शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कमीशन प्रपत्र के भाग-2 में, "निर्यात पुष्टीकरण" के आधार पर दी जाएगी।

(ग) भारतीय मर्दों के अधीन आने वाली मर्दों: उन भारतीय मर्दों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परंपरागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यू.एस.ए. यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को निर्यात के लिए पोतानदान सीमा शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुमित किया जाएगा।

20.(क) निर्यात प्रमाण पत्र, उद्गम प्रमाण पत्र और बीसा.सगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण पत्र परिधान निर्यात संबंधित परिषद् या उनके नाम में विविध प्राधिकृत किया अन्य परिषद् द्वारा जारी किए जाएंगे:—

- (1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय:—(क) निर्यात के अधीन सभी पोशाक/बुनी हुई मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम प्रमाण पत्र।
(ख) सभी गैर नियमित पोशाक/बुनी हुई मर्दों के लिए उद्गम प्रमाण पत्र।

(2) फिनलैंड:— नियमित मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

(3) स्वीडन:— नियमित मर्दों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

(4) आस्ट्रिया:—निर्यात या निगरानी की शर्त के अधीन सूती, पावरलूम/मिश्रित निमित्त पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

(5) नार्वे:— उन श्रेणियों के संबंध में जो विशिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत आती हैं और निगरानी के अधीन श्रेणियों (मिश्रित निमित्त/मिश्रित वासक करघा) के लिए भी निर्यात प्रमाण-पत्र और मूलतः प्रमाण पत्र।

(6) कनाडा:— बुने हुए पावरलूम और मिश्रित-निमित्त मूल की पोशाकों जो निर्यात के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डॉलर मूल्य के परेषण के लिए, निर्यात प्रमाण पत्र।

(7) यू.एस.ए.:—(क) यू.एस. डॉलर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए बीसा।

(ख) यू.एस. डॉलर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण-पत्र।

(ख) हथकरघा प्रमाण पत्र नियमित मर्दों के सगत सभी हथकरघा पोशाकों के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आस्ट्रिया की निर्यात के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्तु समिति प्रमाण पत्र जारी करेगा। जहां तक नार्वे का निगरानी मर्दों के सगत हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, हथकरघा मूल रूप से बनाते हुए परिधान निर्यात संबंधित परिषद् द्वारा एक प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। वस्तु समिति-प्रमाण पत्र के आधार पर परिधान निर्यात संबंधित परिषद् हथकरघा मूल को बताएगा।

21. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

22. संबंधित निर्यात संबंधित परिषद् और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पते निम्न प्रकार से हैं:—

- (1) परिधान निर्यात संबंधित परिषद्, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019
- (2) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधित परिषद्, 612/714, अशोक इस्टेट, 24, माराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- (3) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बॉक्स सं. 11500, बम्बई 400 020

(1) वस्त्र मंजिल,
'बिल्डिंग', 74, डा. एनी बिसेट रोड
बम्बई 400 018

(5) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
बैस्ट ब्लॉक 7, ग्राफ के गुरुम,
नई दिल्ली 110 021

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक
आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th September, 1985

Export Trade Control

PUBLIC NOTICE NO 28-ETC(PN)/85

Sub.—Scheme for exports under OGL-3 of garments and knitwear to USA, EEC Member States, Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1986 to 31st December, 1986.

F. No. 2/65-A/85E.I.—This scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear items to USA, EEC Member States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic Denmark and Greece), Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada for the period 1st January, 1986 to 31st December, 1986.

2. Agents for administration of the scheme. (i) Unless otherwise directed, the Apparel Export Promotion Council (AEPIC), New Delhi will allocate export entitlements and do the necessary certification for the export of all garments and knitwear covered by this scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC) New Delhi. However, in respect of woollen knitwear necessary certification will continue to be done by the Apparel Export Promotion Council. List of categories of Textile products covered under this scheme are available with the Apparel Export Promotion Council and the Wool and Woollen Export Promotion Council. Government reserves the right to make changes, as considered appropriate with regard to the agencies for the administration of the scheme.

(ii) Export entitlement will be allowed only to exporters who are registered with competent Registering Authorities.

3. Systems and Quantum of Allotment. (i) Quantities for export will be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them:—

Systems

per cent of the annual level

- | | |
|---------------------------|----|
| (a) Past Performance | 65 |
| (b) FCFS Small Orders | 25 |
| (c) Manufacturer Exporter | |

(d) Central State Corporations

3

(ii) Government reserves the right to use flexibilities provided in the Bilateral agreement as considered appropriate.

4. Division of the allotment year and apportionment of quantities among periods (i) in the case of PPE system the year will be divided into two periods. The first period will be from 1st January to 30th April and the second period will be from 1st May to 30th September. A minimum of 50 per cent of the total allotment made should be utilised within the first period; the un-utilised balance of the 50 per cent would be deemed to be automatically surrendered unless otherwise carried over with enhanced guarantee. For the Manufacturer Exporters Entitlement system there will be one period from 1st January to 30th Sept. The Allotment may be valid beyond 30th Sept. as per provisions in Para 15(iii). The entire allocation under Past Performance and Manufacturer Exporter System would have to be utilised before 30th Sept. 1986. The un-utilised balance, if any, would be deemed to be automatically surrendered unless its validity is extended in accordance with the provisions in Para 15(iii).

(ii) In the case of Central State Corporations and First Come First Served Small Order System the year will be divided into three-4 monthly periods namely January-April, May-August and September-December, in the case of woven items, and into two periods January-August and September-December for knitted items. In the case of Central State Corporation system quantities for woven items will be distributed among the 3 periods in the ratio of 50:35:15 and in the case of FCFS system 15 per cent of the annual level will be allotted in the first period, 7 per cent in the second period and 3 per cent in the third period whereas the quantities for knitted items will be distributed between the two periods in the ratio of 85:15 in both the systems.

(iii) The above percentage may be re-adjusted by the Govt. depending upon trends in the overseas market.

5. Reservation of segments: (i) In the case of First Come First Served Small Order and Central State Corporations systems wherever knitted garments are clubbed with woven garments for allocation, 10 per cent of the quantity available would be reserved for knitted garments.

(ii) For children's garments 10 per cent of the quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories.

This will be amounted by the Textile Commissioner.

6. Past Performance system. (i) Agency for calculation of past performance entitlements: The agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be the Apparel Export Promotion Council, New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of the Apparel Export Promotion Council.

(ii) Eligibility for past performance entitlement system. An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance System for the year 1986 only if he has export performance in the relevant country/category during any two years of the three years viz. 1983 1984 and January-June, 1985.

(iii) Base period and ceiling: The past Performance Entitlement will be determined for each country/category combination pro-rata on the basis of average annual exports during the base period of 1983, 1984, and January-June, 1985. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling equivalent to the average annual export performance of the exporter during the base period in the relevant country/category. In the case of any subsequent changes in the entitlement of any individual exporter the entire exercise of pro-rata quantity need not be re-opened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporter.

(iv) Transferability of past performance entitlement

Past performance Entitlement will be transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time upto 30th September, 1986 subject to the following terms and conditions:—

(a) All transfers of Past Performance Entitlement would only be allowed on submission of 10 per cent Bank Guarantee by the transferee.

(b) Transferee would be allowed 60 days to export of transferred quantity.

(c) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country/category either in full or in part will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country/category.

(e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under First Come First Served small order system in a particular country/category will not be eligible to effect any transfer from his Past Performance Entitlement in that country/category after he obtains such Small Order Entitlement.

(f) The transferror entitlement in the hands of the transferee will be subject in all other respects, to the terms and conditions as those applicable to the transferror.

7. First come First Served small order system. Under this system, quantities will be allotted on First Come First Served basis against applications supported by firm contracts and Letter of Credit. Letters of Credit should be valid, operative and irrevocable. Letters of Credit should clearly mention the orders against which LCs have been opened. Allotment of

quantities shall be made only for small orders which are within the quantitative limit fixed by the Textile Commissioner for different country/category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this system will be subject to the following conditions:—

- (i) The exporters should have been registered with the Apparel Export Promotion Council (or W&WEPC for woollen knitwear) on or before 31st December 1983 to be eligible to apply for allocation under this system during 1986.
- (ii) Only one application will be admissible from an exporter for one country/category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such application is within the stipulated quantitative ceiling. The application for the 1st period will be received on 1-12-1985 but allotments will be made from 1-1-1986.
- (iii) Allotment under this system shall be valid for a period of 60 days. In the third period allotment shall be valid only upto 31st December 1986.
- (iv) Allotment will be granted on First Come First Served basis, and on a day when available quantities are over subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.
- (v) An exporter with Past Performance Entitlement will be eligible for applying under this system after exporting atleast 50 per cent of his Past Performance Entitlement in the relevant country/category, as worked out according to Para 6(iii). He will also have the option of surrendering the entire balance of Past Performance Entitlement that he holds in the relevant country/category and then applying under First Come First Served Small Order system, provided he has not effected any transfer from his Past Performance Entitlement in that country/category.
- (vi) A Manufacturer Exporter Entitlement holder will have to utilise or surrender his such entitlement fully before becoming eligible to apply under the First Come First Served Small Order System.
- (vii) For the purpose of allotment under the FCF Small Order system, an applicant should give an affidavit that none of his associate concerns as defined in paragraph 120 of the Handbook of Import-Export Procedures 1985-86 has applied for allotment under this system and also that no other proprietorship concern under his proprietorship has applied for allotment under this system. Further, the applicants for 1st period allotment should also give an affidavit that none of their associate concern has any past performance entitlements.

8. Manufacturer Exporters system: In this system quantities to the extent of 7 per cent of the annual level will be allotted to Manufacturer Exporters subject to the condition that the total allocation for a Manufacturer Exporter under Past Performance and the Manufacturer Exporter system will not exceed 110 per cent of his average annual Past Performance, as worked out according to the Para 6(iii). 50 per cent of level will be allotted on the basis of past performance and the remaining 50 per cent on the basis of manufacturing capacity of manufacturer exporters. The Textiles Commissioner will decide the eligibility for allotment under this system for which he will issue detailed instructions.

9. Central/State corporations system: For Corporations under the control of the Central/State Union Territory Governments and Apex, Co-operative Handloom Marketing Societies at the Central/State levels, there will be a special allocation not exceeding 3 per cent of the annual level. The allocation will however, be made only for direct exports by these corporations/Apex Societies. The allocation under the system will be subject to the condition that the Central/State Corporation should have production under its aegis. If such a Corporation does not have production facilities under its aegis, it should not get the manufacturing done by listed exporters or by manufacturers who are already supplying to any other exporters. These conditions will, however, not apply to slow moving items. The Corporations/Apex Societies will also be eligible for allotment of quantities under Past Performance and First Come First Served Small Orders Systems of allotment subject to fulfilment of conditions laid down in the Policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporations/Apex Societies.

10. Slow moving Items. For identification of slow moving items performance during the first four months of 1985 and the performance during 1984 will be taken into account. An item would be termed slow moving if during the period under reference its exports have not exceeded 75 per cent of the level earmarked for the first four months of 1985 or during the entire year 1984. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, the following relaxations will be available in respect of items declared slow moving—

- (i) Registration with AEPC/W&WEPC can be done at any time during the year for eligibility under the First Come First Served Small Order System.
- (ii) There shall be no compulsory Letter of Credit stipulation.
- (iii) The exporter shall have to furnish 1 per cent Earnest Money Deposit/Bank Guarantee in lieu of normal Bank Guarantee/Earnest Money Deposit.
- (iv) The quantitative ceiling stipulated in the case of First Come First Served Small Orders application shall not be enforced. There

shall also not be any restrictions on the number of applications that can be submitted in one day in the country/category.

- (v) Certification of shipping bills under First Come First Served Small Orders systems for slow moving items will be valid upto the end of the allotment period during which the application has been submitted.

- (vi) There may be separate floor prices for children's garments in slow moving items.

11. Allocation of categories not subject to specific limit in USA. A specified quantity under the categories not subject to specific limit but subject to overall group II limit in USA will be allocated under all the four systems like any other category. All conditions applicable to allocation of sensitive items under the above systems will also be applicable to allocation of such categories. Such allocations will also be subject to any other condition that may be stipulated in the event of limitations on exports being introduced on any of these categories. Conversion of Past Performance Entitlement and Manufacturer Entitlement for items under specific or temporary restraint into items not covered by such restraints and also conversion among non-restraint items in terms of square yards equivalence (SYE) may be permitted by the Apparel Export Promotion Council within the Group ceiling.

12. Minimum Export (Floor Prices): Normally, there shall be only one floor price for each country/category. The Textile Commissioner will prescribe floor prices. In determining them he will take into account all relevant factors including the fact whether a particular item has been identified as slow moving one or not.

13. Validity period of certification of export entitlement: A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days except in the case of First Come First Served Small Order system where the validity period will be as stipulated in Para 7(iii).

14. Letter of credit. The allocation for all garments and knitwear will be made on letter of credit terms. Letter of Credit should be operative, valid and irrevocable. In the case of First Come First Served Small Orders and Central/State Corporations system, Letter of Credit should be submitted along with the application. In the case of Past Performance Entitlement and Manufacturer Exporter Entitlement system, Letter of Credit should be produced at the time of obtaining certification. Letters of Credit will not be required for slow moving items declared as such in terms of para 10.

15. Earnest money deposit/bank guarantee and forfeiture thereof : (i) In the case of Past Performance system exporter shall not be required to furnish Earnest Money Deposit or Bank Guarantee for quantity shipped during the period January-April, 1986. He should utilise 50 per cent of the Past Performance Entitlement on or before 30-4-86. The un-utilised portion of this entitlements can be carried over with Bank Guarantee of 15 per cent during the second

period. He should utilise 75 per cent of the Past performance Entitlement on or before 31-7-86. The un-utilised portion of this entitlement can be carried over with Bank Guarantee of 15 per cent upto 30-9-86.

(ii) In the case of Manufacture Exporter System, an exporter shall not be required to furnish any Earnest Money Deposit/Bank Guarantee for quantity shipped during the period January-April 1986. He shall be required to furnish Earnest Money Deposit/Bank Guarantee to the extent of 10 per cent of the FOB value of export entitlements retained beyond 30-4-86. Last date for production of such Earnest Money Deposit/Bank Guarantee would be 30-4-86.

(iii) The validity of Past Performance Entitlement and Manufacturer Exporters Entitlement would be restricted to 30th September. However, validity can be extended upto 31st December, 1986 against specified contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit/Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iv) In the case of First Come First Served Small Order and Central/State Corporations system, an exporter shall be required to give performance bond backed by Earnest Money Deposit/Bank Guarantee @ 5 per cent of the FOB value on the quantities applied for.

(v) An exporter who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allocated to him on or before 30-9-86 in the Manufacturers Exporter System or in a particular period under the other systems of allotment excluding Past Performance Entitlement will not be liable to forfeiture of EMD/BG. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of EMD/BG in full. In the cases of PPE System, EMD/BG will be forfeited unless 90 per cent of the quantity covered by such EMD/BG is utilised. In the case of revalidation under Past Performance Entitlement and Manufacturer Exporter system beyond 30-9-86 the entire amount of EMD/BG will be forfeited unless 90 per cent of the quantity covered by individual contracts is utilised. These provisions will be subject to conditions of force majeure wherever these arise.

(vi) In the case of Central/State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period the exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension would be filed within one month of the end of the relevant allotment period. In such cases exporter will have to furnish EMD/BG at double the normal rate for balance quantity. In the case of his failure to export fully, the EMD/BG will be liable to be forfeited in full.

(vii) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

16. Appeal against forfeiture of EMD|BGs. For the purpose of giving the consideration to representations made by the exporters against forfeiture of EMD BG for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD|BG by the AEPC the export concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner Bombay within 15 days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by the Appellate Committee constituted by the Government.

17. Merger of available quantities on 30th September. Notwithstanding anything contained elsewhere in this public Notice all balanced quantities available as on 30th Sept. from unallocated levels or surrenders from all systems shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the First Come First Served Small Order system without any reservation for different segments.

18. Supervision of allocation of export entitlement. The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representative of the concerned EPCs as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

19. Clearance by Customs. (A) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA. Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Appeal Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

(B) Handloom Garments : In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada, Cotton handloom garments to Australia, surveillance items to Norway are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

(C) Garments falling under 'India Items'. In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of Indian shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development—Commissioner (Handicrafts).

20. (A) Export Certificate, Certificate of origin and Visa : The following certificates required under the relevant bilateral textile agreement will be issued by the Appeal Export Promotion Council or any other Agency duly authorised in this behalf:—

- (i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of origin for all garment|knitwear items under restraint.
- (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments|knitwear items.
- (ii) Finland—Export Certificates for restrained items.
- (iii) Sweden—Export Certificates for restrained items.
- (iv) Austria—Export Certificates for cotton powerloom|millmade garments subject to restraint or surveillance.
- (v) Norway—Export certificate and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits and also categories (millmade|powerloom) under surveillance.
- (vi) Canada—Export Certificate for garments of knitted powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.
- (vii) USA—(a) Visa for all garment|knitwear consignment valued over US \$ 250.
- (b) Exempt certification for consignments valued at US \$ 250 or less.

(B) Handloom Certificate. In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of Cotton handloom garments to Austria the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the bilateral Agreements for such products. In so far as export of handloom garments corresponding to Surveillance items to Norway an export certificate by the AEPC indicating the handloom origin will be required. AEPC will indicate handloom origin on the basis of Textile Committee Certificate.

21. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

22. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.

2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

3. Office of the Textile Commissioner, Post Box 11500, Bombay-400020.

4. Textile Committee, 'Crystal', 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.

5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports